

Daily Current Affairs

Date : 05 June, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'राज-काज' प्रणाली की स्थिति
2.	विश्व दुग्ध दिवस - 2026 (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)
3.	'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के तहत राजस्थान को 6 पुरस्कार
4.	जयपुर में 'भारत टैक्सी' का ट्रायल
5.	'PM ई-बस सेवा योजना' का राजस्थान में संचालन
6.	राज्यसभा चुनाव - 2026 के लिए उम्मीदवार
7.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. कंचन देवी समिति 2. अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइक्लिंग सिटी लीग - 2026 3. लावण्य पुरोहित (राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक) 4. भीम एवं भोपालसागर बांध (राजसमंद)
8.	राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025
9.	भारत का नया मध्यम वर्ग
10.	सौर ऊर्जा क्षमता
11.	नवचार मंत्र पहल
12.	पद्मा बैराज
13.	S-400 वायु रक्षा प्रणाली

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में 'राज-काज' प्रणाली की स्थिति



चर्चा में क्यों?

- जून, 2026 तक राज-काज प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 71 प्रशासनिक विभागों को एकीकृत डिजिटल मंच पर जोड़ा जा चुका है।



मुख्य बिन्दु:

- 'राज-काज' प्रणाली राज्य सरकार का एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ शासन प्रक्रियाओं को अधिक तीव्र, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाया जाता है।

--:2:--

- **विकसित** : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर तक शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करता है।
- इस प्रणाली से 71 विभाग एवं 57,000 से अधिक कार्यालय डिजिटल रूप से जुड़ने से विभागीय समन्वय, निर्णय प्रक्रिया एवं फाइल प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही, कार्य निष्पादन की गति में वृद्धि हुई है।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (अन्य प्रमुख एप्लीकेशन):**
- राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण डिजिटल ऐप्स लॉन्च किए हैं।
- **राजस्थान संपर्क 2.0** : यह एक एकीकृत जन शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनके समाधान की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- **e-Mitra** : यह ऐप राजस्थान सरकार की 600 से अधिक सेवाओं तक डिजिटल पहुँच प्रदान करता है।
- **Raj Cop सिटीजन** : राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित यह ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इसके माध्यम से आपातकालीन मदद मांग सकते हैं, एफआईआर की स्थिति देख सकते हैं और पुलिस को सूचनाएँ दे सकते हैं।
- **शाला दर्पण** : राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा साझा करने का प्रमुख मंच।

विश्व दुग्ध दिवस - 2026 (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)



चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा वर्ष 2001 से प्रति वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है।



मुख्य बिन्दु:

- पशुपालन और डेयरी विभाग की 'बेसिक एनीमल हस्बैंडरी स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद सम्पूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** : 26 नवंबर (यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में मनाया जाता है)

राज्य में दुग्ध उत्पादन :

- **राज्य में दुग्ध संकलन (वर्ष 2025-26 में)** : लगभग 45 लाख लीटर प्रतिदिन।
- **दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता** : विगत 2 वर्ष में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन। डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क में व्यापक विस्तार से दुग्ध उत्पादों के विपणन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए 'सरस' बूथ स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की जा रही है।
- सरस द्वारा भारतीय सेना को प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **भारत के शीर्ष - 5 दुग्ध उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश (15.66 प्रतिशत), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत)। ये सभी राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 54.09 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स :

राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)

- **स्थापना** : 1977 में (राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1965 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत)
- **उद्देश्य** : राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के तहत राजस्थान को 6 पुरस्कार



चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 'पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में 90 लाख से 1.50 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 4 श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए।



मुख्य बिन्दु:

- **पुरस्कार प्राप्तकर्ता :** ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा।
प्रमुख पुरस्कार:
 - **उपभोक्ता श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार :** राजस्थान को 90 लाख से 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
 - **मई माह में रिकॉर्ड प्रदर्शन हेतु पुरस्कार :** राजस्थान ने 'मई 2026' के दौरान पूरे देश में रूफटॉप सोलर प्लांट के सबसे अधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण (इंस्पेक्शन) और वेंडर्स का पंजीकरण दर्ज कराया। इस श्रेणी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 - **जयपुर देश के टॉप - 10 जिलों में शामिल :** सर्वाधिक सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के मामले में जयपुर देश में 7वें स्थान पर रहा।
 - **वेंडर श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार :** रूफटॉप सोलर सेटअप लगाने के लिए 'मिलन सौर ऊर्जा केंद्र' को वेंडर श्रेणी के तहत देश में दूसरा पुरस्कार मिला।
 - उल्लेखनीय है कि मई, 2026 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर वितरण निगमों में 39279 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 27,700 आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया गया, 26,632 रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल हुए और 177 नए वेंडरों को योजना से जोड़ा गया।

Daily Current Affairs

Date : 05 June, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना:

- **लॉन्च** : 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
- **संबंधित मंत्रालय** : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य** : रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना की सुविधा के द्वारा घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- **लक्ष्य** : मार्च, 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024' जारी की है, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ-साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग के प्रावधान किए गए हैं।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी:

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त छत सौर संयंत्र क्षमता	सब्सिडी सहायता
0-150	1-2 किलोवाट	₹30,000 से ₹60,000 तक
150-300	2-3 किलोवाट	₹60,000 से ₹78,000 तक
300 से अधिक	3 किलोवाट से अधिक	₹78,000

--6--

जयपुर में 'भारत टैक्सी' का ट्रायल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जयपुर में देश की पहली सहकारी मॉडल (Cooperative Model) पर आधारित कैब सेवा 'भारत टैक्सी' का ट्रायल रन शुरू हुआ।

मुख्य बिन्दु:

- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत, भारत टैक्सी की स्थापना 6 जून, 2025 को सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय स्तर के 8 संस्थानों द्वारा की गई, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 5 फरवरी, 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया।
- भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह पहल "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ओला और उबर जैसे कमर्शियल एग्रीगेटर्स के मुकाबले ड्राइवरों के स्वामित्व वाला एक डिजिटल विकल्प खड़ा करना है।

कार्यप्रणाली :

- यह मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत स्थापित प्लेटफॉर्म है, जो ड्राइवरों को 'ड्राइवर-पार्टनर' के बजाय 'सारथी-मालिक' का दर्जा देता है।
- यह प्लेटफॉर्म जीरो-कमीशन मॉडल पर चलता है। ऐप पर कोई सुविधा शुल्क या प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाता, जिससे पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलता है।
- **महिला सुरक्षा प्राथमिकता :** भारत टैक्सी ने सारथी के रूप में महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने हेतु महिलाओं को महिला-चालित टैक्सी विकल्प किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करने के अलावा SOS, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और समर्पित 24x7 ग्राहक सहायता जैसी सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करते हुए महिला-केंद्रित 'सारथी दीदी' फीचर लॉन्च किया है।



'PM ई-बस सेवा योजना' का राजस्थान में संचालन



चर्चा में क्यों?

- 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना' के तहत राजस्थान के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव है।

Cabinet Decisions
16 August 2023

PM-eBus Sewa

Cabinet nod to "**PM-eBus Sewa**" for augmenting city bus operation by **10,000 e-buses**

- Estimated cost of Rs.57,613 crore, of which Rs.20,000 crore to be provided by the Central government
- Scheme to support bus operations for 10 years
- Scheme to cover cities of 3 lakh and above population
- All Capital cities of UTs, NE Region and Hill States to be included
- Priority to cities having no organized bus service
- Scheme to generate 45,000 to 55,000 direct jobs

1/2

--:8:--

Daily Current Affairs

Date : 05 June, 2026



मुख्य बिन्दु:

■ योजना के तहत चयनित शहर:

शहर	प्रस्तावित बसों की संख्या
जयपुर	450
जोधपुर	125
बीकानेर	125
अजमेर	100
अलवर	100
कोटा	100
उदयपुर	50
सीकर	50
भीलवाड़ा	50

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स :

पीएम ई-बस सेवा योजना:

- स्वीकृति : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 16 अगस्त, 2023 को।
- सम्बंधित मंत्रालय : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- योजना का उद्देश्य : शहरी सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाना। साथ ही, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
- योजना के तहत देश भर के 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी।
- यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी।

--:9::--



UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

Daily Current Affairs

Date : 05 June, 2026



CIVIL
SERVICES

राज्यसभा चुनाव - 2026 के लिए उम्मीदवार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

मुख्य बिन्दु:

नवघोषित उम्मीदवार	पार्टी का नाम	कार्यकाल पूर्ण करने वाले सांसद	पार्टी का नाम
सतीश पूनिया	भाजपा	राजेंद्र गहलोत	भाजपा
अलका गुर्जर	भाजपा	रवनीत सिंह	भाजपा
नीरज डांगी	कांग्रेस (पुनः उम्मीदवार)	नीरज डांगी	कांग्रेस

राजस्थान से राज्यसभा सदस्य (जून, 2026 तक)

क्र.सं.	नाम	पार्टी	कार्यकाल
1.	नीरज डांगी	कांग्रेस	22 जून, 2020 - 21 जून, 2026
2.	राजेन्द्र गहलोत	भाजपा	22 जून, 2020 - 21 जून, 2026
3.	रवनीत सिंह	भाजपा	27 अगस्त, 2024 - 21 जून, 2026
4.	घनश्याम तिवाड़ी	भाजपा	05 जुलाई, 2022 - 04 जुलाई, 2028
5.	रणदीप सिंह सुरजेवाला	कांग्रेस	05 जुलाई, 2022 - 04 जुलाई, 2028
6.	मुकुल बालकृष्ण वासनिक	कांग्रेस	05 जुलाई, 2022 - 04 जुलाई, 2028
7.	प्रमोद कुमार	कांग्रेस	05 जुलाई, 2022 - 04 जुलाई, 2028
8.	चुन्नीलाल गरासिया	भाजपा	04 अप्रैल, 2024 - 03 अप्रैल, 2030
9.	मदन राठौड़	भाजपा	04 अप्रैल, 2024 - 03 अप्रैल, 2030
10.	सोनिया गांधी	कांग्रेस	04 अप्रैल, 2024 - 03 अप्रैल, 2030

--:10:--



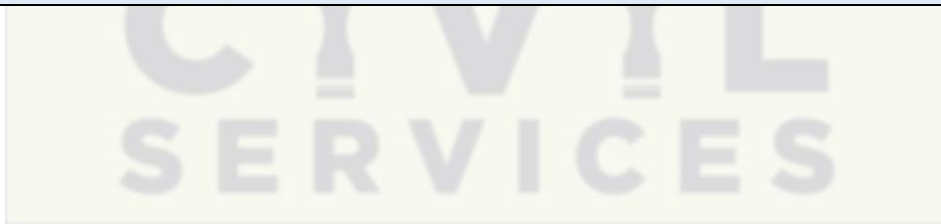
UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	कंचन देवी समिति ■ हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की सीमाओं को पुनर्परिभाषित (Redefine) करने और पर्यावरणीय समीक्षा के लिए एक 5-सदस्यीय समिति का गठन किया। ■ समिति की अध्यक्ष : भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी। ■ इस उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति को 31 अगस्त, 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ■ समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कम किया जा सकता है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। ■ समिति रिपोर्ट में प्रयुक्त ऊंचाई मानदंडों के वैज्ञानिक आधार का भी आकलन करेगी और यह मूल्यांकन करेगी कि क्या अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियामक तंत्र पर्याप्त हैं।
2.	अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइक्लिंग सिटी लीग - 2026 ■ आयोजन : 1 से 14 जून, 2026 तक। ■ राजस्थान के 8 शहरों में इस लीग का आयोजन किया जाएगा। (जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, दौसा और बीकानेर) ■ आयोजक : साइक्लिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (CFI) द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) और युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से। ■ ASMITA : अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ■ उद्देश्य : इस महिला साइक्लिंग लीग का उद्देश्य बालिकाओं एवं महिलाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, फिटनेस को प्रोत्साहित करना तथा महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।



3.	लावण्य पुरोहित (राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक) ■ फलोदी निवासी लावण्य पुरोहित ने हाल ही में गुजरात में आयोजित 4th PAFI राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप - 2026 में स्वर्ण पदक जीता। ■ भार वर्ग : जूनियर 75 किलोग्राम। ■ आयोजन स्थल : राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात। ■ आयोजन अवधि : 29 मई से 2 जून, 2026 तक।
4.	भीम एवं भोपालसागर बांध (राजसमंद) ■ हाल ही में, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने राजसमंद स्थित भीम एवं भोपालसागर बांधों तथा इनकी नहर प्रणालियों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। ■ बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इन दोनों बांधों एवं इनकी नहरों के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई थी। ■ भीम बांध का निर्माण वर्ष 1950 में तथा भोपालसागर बांध का निर्माण वर्ष 1956 में किया गया था। दोनों परियोजनाओं से वर्तमान में कुल 931 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।





राष्ट्रीय परिदृश्य



राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है, जिनमें भारत की 42 पंचायतें शामिल हैं।



--:13:--



मुख्य बिन्दु:

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

- **परिचय :** राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार स्थानीय स्वशासन संस्थानों को सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।
- **कार्यान्वयन ढांचा:** ये पुरस्कार पंचायतों को प्रोत्साहन देने (IOP) योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का घटक है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर ₹50 लाख से लेकर ₹5 करोड़ तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं।
- कर्नाटक को सबसे अधिक पुरस्कार (6 पुरस्कार) प्राप्त हुए, उसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 2025 के लिए 5-5 पुरस्कार मिले।

पुरस्कारों की श्रेणियाँ

- **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है।
- **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** समग्र आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रदान किया जाता है।
- **पुरस्कार यहाँ दिए जाते हैं:**
 - जिला पंचायत स्तर
 - ब्लॉक पंचायत स्तर
 - ग्राम पंचायत स्तर पर।



आर्थिक घटनाक्रम



भारत का नया मध्यम वर्ग

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- बढ़ती आय, शहरीकरण और आर्थिक संवृद्धि के कारण भारत के मध्यम वर्ग का आकार तेजी से बढ़ रहा है।



मुख्य बिन्दु:

- 1995 से 2021 के बीच भारत के मध्यम वर्ग का आकार प्रत्येक वर्ष 6.3% की दर से बढ़ा है और अब यह देश की कुल आबादी का लगभग 31% है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, 2030-35 तक भारत के मध्यम वर्ग का आकार चीन से भी बड़ा हो जाएगा।

मध्यम वर्ग का आर्थिक योगदान

- देश की घरेलू खपत को बढ़ाने वाला मुख्य करक: विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, भारत का मध्यम वर्ग 2026 में कुल उपभोग व्यय का 80% हिस्सा वहन कर रहा था, जो 2036 तक बढ़कर 93% हो जाएगा।
- मानव पूंजी का विकास: यह वर्ग शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं में निवेश के माध्यम से कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाता है।
- उद्यमिता को बढ़ावा : यह वर्ग स्टार्टअप, लघु व्यवसायों और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- राजस्व में योगदान: आयकर और जीएसटी के भुगतान तथा विभिन्न उत्पादों में निवेश के माध्यम से यह वर्ग सरकार के राजस्व और पूंजी निर्माण में योगदान देता है।
- सामाजिक स्थिरता: यह वर्ग सामाजिक उन्नति और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करता है।

चुनौतियां

- **आय में ठहराव:** देश की आर्थिक प्रगति के बावजूद लोगों की वास्तविक आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।
- **जीवन-यापन की बढ़ती लागत:** आवास, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, शिक्षा और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें उनकी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।
- **नौकरी की असुरक्षा:** ऑटोमेशन, AI और गिग वर्क के कारण भविष्य की नौकरियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है।
- **कर्ज का बोझ:** लाइफस्टाइल और दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज लेकर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनकी बचत कम हो रही है।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना:** सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मध्यम वर्ग के लिए सरकारी पहलें

- **वित्तीय सुरक्षा:** 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है, जीएसटी दरों में कमी की गई है।
- **वित्तीय समावेशन और उद्यमिता:** पीएम जन-धन योजना (PMJDY), जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity) जैसी योजनाएं आरंभ की गई हैं।
- **आवास:** पीएम आवास योजना-शहरी और स्वामिह (किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवासीय परियोजना) कोष जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं।
- **परिवहन के बेहतर साधन :** मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, उड़ान योजना संचालित की जा रही है।
- **स्वास्थ्य-देखभाल:** ईट राइट इंडिया, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई (PMJAY)।

सौर ऊर्जा क्षमता

(स्रोत: HINDUSTAN TIMES)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार भारत 2025 में सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर रहा।



-:17:-



मुख्य बिन्दु:

- हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 में 37 गीगावाट (GW) से अधिक की सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इस तरह वह संयुक्त राज्य अमेरिका (34 GW की क्षमता वृद्धि) से आगे निकल गया है।
 - भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 155 गीगावाट को पार कर गई है।
 - दिसंबर 2025 तक, देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन का योगदान 51.93% हो गया।
 - 'नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026' के अनुसार, चीन और अमेरिका के बाद भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें**
- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** यह घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है।
 - **अवसंरचना विकास:** 55 सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है। साथ ही, उपभोक्ताओं तक इनकी आपूर्ति के लिए बिजली उत्पादन स्थल से मुख्य ग्रिड तक 'हरित ऊर्जा गलियारा' का दूसरा चरण शुरू किया गया है।
 - **सौर ऊर्जा उपकरणों का देश में विनिर्माण:** सौर ऊर्जा उपकरणों के लिए 'ALMM' (मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत सूची में शामिल उपकरणों की देश के विनिर्माताओं से ही खरीद अनिवार्य कर दी गई है।
 - **विश्व को मार्गदर्शन:** भारत 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) का नेतृत्व कर रहा है, ताकि विश्व भर में सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सके।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

नवचार मंत्र पहल

(स्रोत: DD NEWS)

- चर्चा में क्यों?
- नवचार मंत्र एक राष्ट्रीय पहल है जिसे केंद्रीय मंत्री ने IIT दिल्ली में शुरू किया था।



- मुख्य बिन्दु:
- नवचार मंत्र पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसे राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
 - इसे रणनीतिक रूप से टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण भारत से उत्पन्न होने वाले जमीनी स्तर के नवाचारों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और उनका विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे स्थानीय रचनाकारों और राष्ट्रीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की खाई को पाटा जा सके।

प्रमुख विशेषताएँ

- **लक्षित जनसांख्यिकी:** यह कार्यक्रम आकांक्षी जिलों और कम विकसित ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 55 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए खुला है।
- **पात्रता:** लचीले मानदंडों के तहत, ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके विचार सत्यापन या प्रारंभिक प्रोटोटाइप चरणों में हों, पंजीकृत कॉर्पोरेट इकाई या तैयार बाजार उत्पाद की आवश्यकता नहीं है।

--:19:--



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



पद्मा बैराज

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- बांग्लादेश ने राजबारी जिले में पद्मा नदी पर पद्मा बैराज नामक एक विशाल नदी परियोजना को मंजूरी दी। पद्मा नदी गंगा नदी का बांग्लादेशी हिस्सा है।



मुख्य बिन्दु:

पद्मा नदी

- भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की यह मुख्य वितरिका है।
- पद्मा नदी दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है, यमुना नदी (निचली ब्रह्मपुत्र) से मिलती है, और बाद में मेघना नदी में विलीन हो जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली, गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा का एक प्रमुख हिस्सा है।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

S-400 वायु रक्षा प्रणाली

(स्रोत: THE HINDU)



चर्चा में क्यों?

- रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन सौंपी।



मुख्य बिन्दु:

- भारत और रूस के बीच 2018 में 5.43 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को पांच S-400 रेजीमेंटल सिस्टम्स मिलने थे। वर्तमान S-400 आपूर्ति उसी समझौते का हिस्सा है।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने पांच और S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रणाली भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का एक प्रमुख आधार है।

-:21:-

- रूस से भारत द्वारा S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद के कारण अमेरिका के CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट) के तहत प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका उत्पन्न हुई थी। हालांकि, अमेरिका ने अब तक भारत पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं।

S-400

- **विकास:** यह रूस द्वारा विकसित 'लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल' (SAM) प्रणाली है। इसे नाटो देश 'SA-21 गोलर' भी कहते हैं।
- **एकीकृत प्रणाली:** इसमें उन्नत रडार, मिसाइल लॉन्चर, कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और लक्ष्य की पहचान करने वाली स्वायत्त प्रणालियां शामिल हैं।
- **बहुस्तरीय सुरक्षा:** यह प्रणाली 40 किमी, 120 किमी, 250 किमी और 400 किमी की मारक क्षमता वाली चार तरह की मिसाइलों का उपयोग करती है।
- **क्षमता:** यह विमान, स्टील्थ विमान, ड्रोन (UAV), क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है।
- **खतरों का पता लगाना:** यह प्रणाली 600 किमी की दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकती है।
- **AI सक्षम:** S-400 में अब AI-आधारित निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। इससे खतरों की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देना और लक्ष्य चुनना और अधिक आसान हो गया है।

अन्य प्रमुख रक्षा प्रणालियां

- S-500 प्रोमेटे (रूस)
- **THAAD (संयुक्त राज्य अमेरिका):** टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (THAAD)
- आयरन डोम (इज़राइल)
- पैट्रियट PAC-3 (संयुक्त राज्य अमेरिका)
- HQ-9 (चीन)